



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|----------|--|
| सं. 226] | नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 29, 2017/भाद्र 7, 1939 |
| No. 226] | NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 2017/BHADRA 7, 1939 |

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2017

केस सं. एसएसआर - 09/2017

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मैट्रोनिडाजोल" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।

यह जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में सुनवाई की जा रही रिट याचिका सं. डब्ल्यू पी (सी) सं. 7464/2017 के अन्तिम परिणाम के अध्यक्षीन होगी।

फा. सं. 7/6/2017-डीजीएडी.—1995 में यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 29 जुलाई, 1999 की अधिसूचना सं. 17/1/99-डीजीएडी के तहत चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मैट्रोनिडाजोल" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत की और दिनांक 21 फरवरी, 2000 की अधिसूचना सं. 17/1/99-डीजीएडी के तहत अन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। मूल जांच में दिनांक 17 अप्रैल, 2000 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 44/2000-सीमा शुल्क के तहत अन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

प्राधिकारी द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2000 की अधिसूचना के तहत न्तिम जांच परिणाम अधिसूचित किए गए और राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2000 अधिसूचना सं. 115/2000-सीमा शुल्क के तहत संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. प्रथम निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में प्राधिकारी ने दिनांक 5 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना सं. 15/9/2003-डीजीएडी के तहत अपने अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचित किए और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की। प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 15 जून, 2006 की अधिसूचना सं. 61/2006- डीजीएडी के तहत पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

3. द्वितीय निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में प्राधिकारी ने दिनांक 20 जून, 2011 की अधिसूचना सं. 15/18/2010-डीजीएडी के तहत अपने अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचित किए और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की। प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2012 की अधिसूचना सं. 40/2012-डीजीएडी के तहत पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

4. मैसर्स हुबेई हांगयुआन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड जिसे पहले मैसर्स हुबेई हांगयुआन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, की ओर से निर्यातक का नाम बदलने के अनुरोध पर कराई गई मध्यावधिक समीक्षा के अनुसरण में प्राधिकारी ने दिनांक 07 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. 15/11/2015-डीजीएडी के तहत उपरोक्त बदलाव की सिफारिश करते हुए अपने अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचित किए। केन्द्र सरकार ने दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 की अधिसूचना सं. 19/2012-डीजीएडी के तहत उपरोक्त परिवर्तन को अधिसूचित किया।

5. यतः मैसर्स आरती ड्रग्स लिमिटेड (जिसे आगे 'याचिकाकर्ता' कहा गया है) ने अधिनियम और नियमों के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत प्रमाणित याचिका दाखिल की है जिसमें चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना तथा घरेलू उद्योग को उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना का आरोप लगाया गया है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

6. यतः प्राधिकारी ने इस याचिका की विधिवत जांच की है और उस जांच के आधार पर दिनांक 22 अगस्त 2017 को एक आदेश जारी किया है कि 'उन्होंने इस अवस्था में चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "मैट्रोनिडाजोल" के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करना उपयुक्त नहीं पाया' जिससे उन्होंने याचिका को अस्वीकार कर दिया।

7. और याचिकाकर्ता यतः मैसर्स आरती ड्रग्स लिमिटेड ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका सं. डब्ल्यू पी (सी) सं. 7464/207 और सी एम सं. 30761/2017 दाखिल की। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 25 अगस्त, 2017 के आदेश के तहत निदेश दिया है कि इस मामले में प्राधिकारी अधिक से अधिक 29 अगस्त, 2017 तक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करे। आदेश का अंश इस प्रकार से है :

"3. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामले में पाटन रोधी शुल्क समाप्त होने की तारीख 29 अगस्त, 2017 है, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के मामले में अधिक से अधिक 29 अगस्त, 2017 तक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए प्रतिवादियों को को निर्देश देता है। निर्णायक समीक्षा अधिसूचना में यह स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि यह कार्यवाही रिट याचिका के अन्तिम जांच परिणामों के अध्यधीन होगी। यह आदेश पक्षकारों के अधिकारों और शर्तों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है और अगले आदेशों तक जारी रहेगा।

4. जहां तक पाटनरोधी शुल्क जारी रहने का प्रश्न है..... प्रतिवादियों की ओर से वकील निर्देशों के लिए समय की मांग करते हैं।”

8. माननीय उच्च न्यायालय के के उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में एट्ट्वारा निम्नलिखित ब्यौरों के साथ एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की जाती है :

शामिल देश

9. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

10. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “मैट्रोनिडाजोल” है। मैट्रोनिडाजोल एक एंटी डायरिया और एंटी माइक्रोबायल ड्रग है। इसे अमीबियासिस ट्राइकोमानीसिस, सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव इंफेक्सन, गारडियासिस, अक्यूट अल्सरेटिव और जिंजिवाइटिस, अनैरोबिक माइक्रो फोरमेसन के कारण हुए इंफेक्सन के अनैरोबिक बैक्टीरियोसिस उपचार में प्रयोग में लाया जाता है।

11. मैट्रोनिडाजोल को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत सीमा शुल्क उप शीर्ष 29332920 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी तरह से उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

12. समान वस्तु के संबंध में नियम 2 (घ) इस प्रकार है :

“समान वस्तु” का अर्थ एक ऐसी वस्तु है जो भारत में पाटन के लिए जांच के अधीन वस्तु के समान न हो या प्रत्येक दृष्टि से उसके जैसी हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य ऐसी वस्तु जो यद्यपि प्रत्येक दृष्टि से समान हो तब भी उसमें जांचाधीन वस्तु से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं हो;”

13. आवेदक ने यह दावा किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई ज्ञात अन्तर नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद में भौतिक और रसायनिक गुणों, निर्माण की प्रक्रिया, कार्यों व उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमतों, वितरण एवं विपणन और टैरिफ वर्गीकरण इत्यादि जैसे मापदंडों के सन्दर्भ में तुलनीय गुण हैं। दाखिल की गई याचिका समीक्षा के लिए और लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए है और समान वस्तु का मामला पहले ही पिछली जांचों में हल कर लिया गया है। पिछली जांचों में प्राधिकारी ने पहले ही यह पाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देश से आयातित वस्तु के समान वस्तु है।

घरेलू उद्योग और आधार

14. यह आवेदन मैसर्स आरती ड्रग्स लिमिटेड, मुंबई द्वारा दाखिल किया गया है। याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। याचिकाकर्ता ने यह स्पष्ट किया है कि आयातों के लिए अग्रिम लाइसेंस है अर्थात् मैट्रोनिडाजोल बेंजोएट के उत्पादन के लिए शुल्क रहित आधार पर है और उससे इस उत्पाद की उनकी निर्यातित बाध्यताएं पूरी होगी। याचिकाकर्ता संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के मामले पर, जो कि प्राधिकारी के दिनांक 22 अगस्त, 2017 के आदेश के तहत निर्णायक समीक्षा शुरू करने के आवेदन को अस्वीकार करने का एक आधार था, वर्तमान में शुरू की जा रही जांच के दौरान लागू नियमों के तहत गुण- अवगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

15. यूनिकैम लैबोरेटरीज लिमिटेड भारत में संबद्ध वस्तु का एक अन्य ज्ञात उत्पादक है। तथापि यूनिकैम प्रमुखतः निर्यात के लिए ही उत्पाद का उत्पादन करता है।

16. यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का करीब 91% है। याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तुओं का बड़ा उत्पादक है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 (3) के साथ पठित नियम 2 (ख) के तात्पर्य से पात्र घरेलू उद्योग है।

पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

17. यतः याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार एक विस्तृत याचिका दाखिल की है, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में प्रवृत्त शुल्कों को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने के लिए तथा यह जांच करने के लिए एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरु करते हैं कि क्या शुल्क समाप्त होने पर घरेलू उद्योग याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका सं. डब्ल्यू पी (सी) सं. 7464/2017 के संबंध में दिनांक 25 अगस्त, 2017 के माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के अन्तरिम आदेश के सन्दर्भ में पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, जिसमें कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निदेश दिया है कि प्राधिकारी इस मामले में अधिक से अधिक 29 अगस्त, 2017 तक अन्य के साथ साथ निर्णायक समीक्षा जांच शुरु करे।

जांच की अवधि

18. जांच की अवधि वर्तमान जांच के प्रयोजन से अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 तक (12 माह) है। तथापि, क्षति मार्जिन की अवधि में अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014, अप्रैल 2014 से मार्च 2015, अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 और जांच की अवधि शामिल है। जांच की अवधि के बाद के आंकड़े पाटन और क्षति की संभावना के निर्धारण के लिए जांचे जाएंगे।

प्रक्रिया

19. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में दिनांक 29 जून 2011 की अधिसूचना सं 15/18/2010- डीजीएडी (दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच के अन्तिम जांच परिणाम) और दिनांक 7 मार्च 2016 की अधिसूचना सं 15/11/2015 – डीजीएडी (मध्यावधिक समीक्षा जांच के अन्तिम जांच परिणाम) शामिल हैं।

20. कथित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

21. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावासों के जरिए उनकी सरकार, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकें :

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,

वाणिज्य विभाग

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5 संसद मार्ग,

नई दिल्ली- 110001

dgad.india@gov.in

22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कोई भी गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी भी पक्षकार को उसके अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करके अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने होंगे।

समय-सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (दिनों 40) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार जिसका पता उपलब्ध नहीं है वह भी चाहे तो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के 40 दिनों के भीतर टिप्पणियां/सूचना प्रस्तुत कर सकता है।

गोपनीय/अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

24. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

25. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय भाग और अगोपनीय भाग की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जाएं।

26. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

27. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

28. प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

29. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

30. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

31. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डॉ. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2017

Case No. SSR - 09/2017

Sub. Initiation of Anti-Dumping Sun Set Review investigation concerning imports of “Metronidazole” originating in or exported from China PR.

This Initiation Notification is subject to the final outcome of the Writ Petition No. WP(C) No. 7464/2017 being heard in the High Court of Delhi, at New Delhi.

F. No. 7/6/2017-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (hereinafter also referred as the Authority) initiated anti dumping investigations on imports of “Metronidazole” (hereinafter also referred as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred as the subject country) vide Notification No. 17/1/99-DGAD, dated 29th July 1999, and recommended imposition of provisional anti dumping duty vide Notification No. 17/1/99-DGAD, dated 21st February 2000. The provisional antidumping duty in the original investigation was imposed on imports of Metronidazole from China PR vide customs notification no. 44/2000-Customs, dated 17th April 2000. The final findings were notified by the Authority vide notification dated 14th July 2000 and the Department of Revenue imposed definitive anti dumping duties on the subject goods from subject country vide Notification No. 115/2000-Customs, dated 31st August 2000.

2. Pursuant to the first sunset review, the Authority notified its Final Findings vide Notification No. 15/9/2003-DGAD, dated 5th April, 2006 and recommended continued imposition of anti-dumping duty, on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country. As per the recommendations of the Authority, the anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 61/2006–Customs, dated 15th June, 2006.

3. Pursuant to the second sunset review, the Authority notified its final findings vide Notification No. 15/18/2010 – DGAD, dated 29th June, 2011 and recommended continued imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country. As per the recommendations of the Authority, the anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 40/2012-Customs, dated 30th August, 2012.

4. Pursuant to mid-term review conducted at the behest of M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Company Ltd. formerly known as M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co. Ltd. requesting change in name of the exporter, the Authority notified final findings recommending the above change vide Notification No. 15/11/2015-DGAD, dated 7th March 2016. The Central Government notified the above change vide Notification No. 19/2012-Customs, dated 20th October, 2011.

5. Whereas, M/s. Aarti Drugs Ltd. (hereinafter referred to as ‘petitioner’) have filed a duly substantiated petition before the Authority, in accordance with the Act and the Rules alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR and consequent injury

to the domestic industry and have requested for review and continuation of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

6. Whereas, the Authority duly examined this petition and based on that examination issued an Order dated 22nd August, 2017 that it *‘does not find it appropriate to initiate the sunset review investigation concerning import of “Metronidazole” originating in or exported from China PR at this stage’*. Thereby, it rejected the petition.

7. Whereas, the petitioner M/s Aarti Drugs Ltd. filed a Writ Petition - WP(C) No. 7464/207 and CM. No. 30761/2017 in the Hon’ble High Court of Delhi. The Hon’ble High Court in its Order dated 25th August, 2017 has directed that the Authority to initiate the SSR in this case no later than 29th August, 2017. The operative portion of order is as below:

“3. Considering that the date of expiry of the Anti-Dumping Duty in the present case is 29th August, 2017, the Court directs the Respondents to initiate the SSR in the Petitioner’s case not later than 29th August, 2017. The SSR notification shall clearly state that the proceedings would be subject to the final outcome of the writ petition. This order is without prejudice to the rights and conditions of the parties and will continue till further orders.

4. As regards the question of Continuation of the ADD... learned counsel for the respondents seeks time for instructions”.

8. In compliance with the above stated directions of the Hon’ble High Court, a sunset review case is hereby initiated with the following details:

Country Involved

9. The subject country in the present sunset review investigation is China PR.

Product under Consideration and Like Article

10. The product under consideration in the present investigation is “Metronidazole”. Metronidazole is anti-diarrhea and anti-microbial drug. It is used in cases of *Amoebiasis*, *Trichomoniasis*, post-operative infection after surgery, giardiasis, acute ulcerative and gingivitis, anaerobic, vaginosis treatment of infection caused by anaerobic micro formation.

11. Metronidazole is an organic chemical classified under Chapter 29 subheading 29332920 of the Custom Tariff Act, 1975. However, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

12. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

“like article” means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;”

13. Petitioner has claimed that there is no known difference in subject goods produced by them and exported from the subject country. The product under consideration produced by the petitioner and imported from the subject country are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The petition filed is for the review and continuation of the anti-dumping duty in force, and the issue of like article has been already dealt with in the previous investigations. In the earlier investigations, the Authority has already held that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the same imported from the subject country.

Domestic Industry & Standing

14. The petition has been filed by M/s. Aarti Drugs Ltd., Mumbai. The petitioner has imported the subject goods from China PR during the period of investigation. The petitioner has explained that the imports are under advance license, i.e. on a duty free basis for production of Metronidazole Benzoate and thereby to meet their export obligation of this product. The petitioner is not related to any other producer/exporter of subject goods in the subject country or any importer in India. The issue of the imports of the subject goods from the

subject country by the petitioner during the POI which was one of the grounds for declining the application for initiation of SSR vide the Authority's Order dated 22 August, 2017 will be taken into consideration on merits as per the applicable Rules during the investigation now being initiated.

15. Unichem Laboratories Ltd. is the other known producer of the subject goods in India. However, Unichem produces the product primarily for export.

16. It is seen that the production of the petitioner is about 91% of the total Indian production. The petitioner in any case is the majority producer of the subject goods in India and is eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Rules of Anti-Dumping Rules.

Initiation of Sunset Review of Anti-Dumping Duty

17. Whereas the petitioner has filed a detailed petition in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry in terms of the interim Order of The Hon'ble High Court of Delhi dated 25th August, 2017 on Writ Petition No. WP (C) No. 7464/2017 filed by the petitioner wherein the Hon'ble High Court has directed that the Authority *inter alia* initiate the SSR in this case no later than 29th August, 2017.

Period of Investigation

18. The period of investigation (POI) is April 2016 – March 2017 (12 months) for the purpose of present investigation. The injury investigation period will however cover the periods April 2013-March 2014, April 2014 - March 2015, April 2015-March 2016 and the POI. The data beyond POI may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

Procedure

19. The present sunset review covers all aspects of Notification No. 15/18/2010 –DGAD, dated 29th June 2011 (final findings of the second sunset review investigation) and Notification No. 15/11/2015-DGAD, dated 7th March, 2016 (final findings of the mid-term review).

20. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules *supra* shall be *mutatis mutandis* applicable in this review.

Submission of information

21. The known exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

Government of India

Ministry of Commerce & Industry

Department of Commerce

Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties

4th Floor, Jeevan Tara Building

5, Parliament Street, New Delhi – 110001

dgad.india@gov.in

22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

Time Limit

23. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/information within 40 days from date of publication of this notification.

Submission of information on confidential basis

24. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either “confidential” or “non-confidential” at the top of each page and accompanied with soft copies.

25. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (2) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

26. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

27. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

28. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

29. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file

30. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

Non-cooperation

31. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority